Impact of Demonetization on Black Money

Dr Varinder Bhatia [1]

ABSTRACT

Demonetization of currency in India is an internationally debated economic issue. It has been carried out to curb the black money menace in India. It had its own pros and cons. Never the less it has increased financial discipline in Indians. This research paper in depth examines demonetization exercise in India and vision ahead to make it constructive.

केंद्र सरकार द्वारा पांच सौ और एक हज़ार के पुराने नोट बंद करने के फैसले पर मिला जुला प्रतिक्रिया देखने में मिल रही है एक तरफ जहा इसे काले धन के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की संज्ञा दी जा रही है वही दूसरी तरफ इसे जल्द बाजी में उठाया गया कदम बताया जा रहा है

इस मुल्क के आम आदमी को आज इतनी समझ है की काला धन सिर्फ विदेशों में ही नहीं जमा करवाया जाता बल्कि इसे लोग बड़े नोटों की शक्ल में घर में भी रखते है कर सुधारों के लिए बनायी गई राजा चेलैया समिति के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में काला धन वह रकम है जिसका लेन-देन परिवारों और कारोबारियों द्वारा जानबूझकर खाताबहियों से दूर रखा जाता है। जिससे सरकार को इस लेन देन की जानकारी नहीं मिल पाती है। इससे राजस्व को भारी नुक्सान होता है इस काला धन देश के भीतर राष्ट्र द्रोह की गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जाता है

इसकी पड़ताल करने से विदित होता है की काले धन की उत्पत्ति कई प्रकार से होती है ,जिनमें मुख्य रूप से आपराधिक स्त्रोतों से प्राप्त किया जाने वाला धन है। जैसे ड्रग्स , घोटाले , आतंकवाद, फिरौतीयों की रकम और तस्करी आदि से प्राप्त धन इसमें मुख्यता शामिल रहता है । कुछेक अंदाजों के मुताबिक के अनुसार विदेशों में भेजे गए धन का 13 से 15 प्रतिशत काला धन आपराधिक जगत के माध्यम से पैदा होता है | इनके अतिरिक्त उन सफेदपोश अपराधियों द्वारा 60 से 65 प्रतिशत धन पैदा किया जाता है जो सत्ता में रहते हुए अपने पदों का दुरूपयोग करते हैं और इस काले धन की उत्पत्ति में अपना संपूर्ण योगदान करते हैं। एक अन्य

[1] Principal SL BAWA DAVCOLLEGE BATALA PUNJAB

प्रकार के काले धन को कुछ व्यावसायिक लोगों अथवा उनकी कम्पनियों द्वारा कर की चोरी करके एकत्र किया जाता है। यह धन विशुद्ध रूप से नकदी होने के कारण बेनामी जमीनें , प्रापर्टी खरीदने में प्रयोग होता है। इस धन का कुछ भाग देश के बाहर हवाला के माध्यम से भी भेजा जाता है। क्यों की कुल काले धन का 80 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा आपराधिक और अवैध स्त्रोतों से आता है। इसलिए यह देश के लिए सर्वाधिक घातक और हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है क्यों की यह धन बड़े नोटों की शक्ल में गुप्त था इस कारन मोदी सरकार का पुराने बड़े नोट बंद करने का तर्क विकृत नहीं लगता है

भारत में नोट यानी के रूपये की कहानी काफी रोचक है जानकारी इकठा करने से पता चलता है की रुपया शब्द का उद्गम संस्कृत के शब्द रुप् या रुप्याह् में है , जिसका अर्थ चाँदी होता है और रूप्यकम् का अर्थ चाँदी का सिक्का है।

रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने भारत मे अपने शासन १५४०-१५४५ के दौरान किया था। शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में जो रुपया चलाया वह एक चाँदी का सिक्का था जिसका भार १७८ ग्रेन (११.५३४ ग्राम) के लगभग था। उसने तांबे का सिक्का जिसे दाम तथा सोने का सिक्का जिसे मोहर कहा जाता था, को भी चलाया।

कालांतर में मुगल शासन के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तीनों धातुओं के सिक्कों का मानकीकरण किया गया।

शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान आरम्भ किया गया 'रुपया' आज तक प्रचलन में है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी यह प्रचलन में रहा, इस दौरान इसका भार ११.६६ ग्राम था और इसके भार का ९१.७ प्रतिशत तक शुद्ध चाँदी थी। १९वीं शताब्दी के अंत में रुपया प्रथागत ब्रिटिश मुद्रा विनिमय दर , के अनुसार एक शिलिंग और चार पेंस के बराबर था वहीं यह एक पाउण्ड स्टर्लिंग का १/१५ भाग था।

१९वीं सदी मे जब दुनिया में सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाएं स्वर्ण मानक पर आधारित थीं तब चाँदी से बने रुपये के मूल्य में भीषण गिरावट आई। संयुक्त राज्य अमेरिका और विभिन्न यूरोपीय उपनिवेशों में विशाल मात्रा में चाँदी के स्त्रोत मिलने के परिणामस्वरूप चाँदी का मूल्य सोने के अपेक्षा बहुत गिर गया। अचानक भारत की

मानक मुद्रा से अब बाहर की दुनिया से अधिक खरीद नहीं की जा सकती थी। इस घटना को 'रुपये की गिरावट' के रूप में जाना जाता है।

पहले रुपया (११.६६ ग्राम) १६ आने या ६४ पैसे या १९२ पाई में बाँटा जाता था। रुपये का दशमलवीकरण १९५७ में भारत मे, १८६९ में सीलोन (श्रीलंका) में और १९६१ में पाकिस्तान में हुआ। इस प्रकार भारतीय रुपया १०० पैसे में विभाजित हो गया। भारत में पैसे को पहले नया पैसा नाम से जाना जाता था। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा जारी की जाती है , जबकि पाकिस्तान में यह स्टेट बैंक आफ़ पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित होता है

सरकार के 500 और हज़ार रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के फ़ैसले के बारे में कहा जा रहा है की इससे काले धन से लड़ाई में सरकार को बड़ी कामयाबी मिलेगी लेकिन ये पहला मौक़ा नहीं है जब बड़े नोट बंद किए गए हैं साल 1946 में में भी हज़ार रुपए और 10 हज़ार रुपए के नोट वापस लिए गए थे फिर 1954 में हज़ार, पांच हज़ार और दस हज़ार रुपए के नोट वापस लाए गए उसके बाद जनवरी 1978 में इन्हें फिर बंद कर दिया गया 1978 में जब ये नोट वापस लिए गए उसके पीछे एक दिलचस्प वाकया है तब जनता पार्टी गठबंधन को सत्ता में आए एक साल ही हुआ था सरकार ने 16 जनवरी को एक अध्यादेश जारी कर हज़ार, पांच हज़ार और 10 हज़ार के नोट वापस लेने का फ़ैसला किया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के ऐतिहासिक दस्तावेज़ (थर्ड वॉल्यूम) में पूरी प्रक्रिया का ब्यौरा दिया गया है 14 जनवरी 1978 को रिज़र्व बैंक के चीफ़ अकाउटेंट ऑफ़िस के वरिष्ठ अधिकारी आर जानकी रमन को फ़ोन कर दिल्ली बुलाया गया

जब रमन दिल्ली पहुंचे तो उनसे एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार बड़े नोट वापस लेने का मन बना चुकी है और इससे संबंधित ज़रूरी अध्यदेश वो एक दिन में बनाएं इस दौरान रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थित केंद्रीय दफ़्तर से किसी भी तरह की बातचीत के लिए सख्त मना किया गया क्योंकि इससे बेवजह की अटकलों के फैलने का डर था

तय समय पर ये अध्यादेश तैयार हो गया और इसे तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया 16 जनवरी की सुबह नौ बजे आकाशवाणी के बुलेटिन में इन बड़े नोटों के बंद होने की ख़बर का प्रसारण हो गया अध्यादेश के मुताबिक़ अगले दिन यानी 17 जनवरी को सभी बैंकों के बंद रहने का ऐलान कर दिया गया उस वक़्त के रिज़र्व बैंक के गवर्नर आई जी पटेल ने अपनी एक किताब में इस घटना के बारे में विस्तार से बताया है पटेल ने लिखा है कि वो सरकार के इस फ़ैसले के पक्ष में नहीं थे उनके मुताबिक़ जनता पार्टी की सरकार के ही कुछ सदस्य मानते थे कि पिछली सरकार के कथित भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाने के लिए ये क़दम उठाया गया है

पटेल ने ये भी लिखा कि जब तत्कालीन वित्त मंत्री एच एम पटेल ने उनसे नोट वापस लेने को कहा तो उन्होंने, वित्त मंत्री को साफ़ कहा था कि इस तरह के फ़ैसलों से मनमाफ़िक परिणाम कम ही मिलते हैं आई जी पटेल ने लिखा कि काले धन को नक़द के रूप में बहुत कम लोग लंबे समय तक अपने पास रखते हैं पटेल के मुताबिक़, सूटकेस और तकिए में बड़ी रकम छुपाकर रखने का आइडिया ही बड़ा बचकाना किस्म का है और जिनके पास बड़ी रक़म कैश के तौर पर है भी वो भी अपने एजेंट्स के ज़रिए उन्हें बदलवा लेंगे

लेकिन इस बार नहीं लगता की सरकार अपने लोह कदम से मुख मोड़ेगी बावजूद इसके की सरकार द्वारा चुनिन्दा नोटों पर आक्रामक रुख अपनाने से पब्लिक को कुछ परेशानिया होना निश्चित था

आने वाले समय में आम आदमी ज्यादातर डिजिटल लेनदेन पर जोर दे और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को बढ़ाने की कोशिश करें। कुल मिला कर सरकार ने काले धन के दन्त दर्द पर रूट कैनाल करने का जोखिम दिखाया है जिसके अछे परिणाम निकलने की उम्मीद करनी चाहिए

References

1. "Withdrawal of Legal Tender Status for 500 and 1000 Notes: RBI Notice (Revised)". Reserve Bank of India. 8 November 2016. Retrieved 8 November 2016.
2. "Notes out of circulation". The Times of India. 8 November 2016.
3. Saikia, Bijoy Sankar (18 Nov 2016). "Demonetisation may drag India behind China in GDP growth, rob fastest-growing economy tag". The Economic Times. Retrieved 2017-01-05.

4. "The dire consequences of India's demonetisation initiative". The Economist. 3 Dec 2016. Retrieved 2017-01-05.
5. Bhatt, Abhinav (8 November 2016). "Watch PM Modi's Entire Speech on Discontinuing 500, 1000 Rupee Notes". NDTV India. Retrieved 8 November 2016.
6. "Demonetisation of Rs. 500 and Rs. 1000 notes: RBI explains". The Hindu. 8 November 2016. Retrieved 10 November 2016.
7. "Sensex crashes 1,689 points on black money crackdown, U.S. election". The Hindu. Retrieved 9 November 2016.
8. "India demonetisation: Chaos as ATMs run dry". Al Jazeera. Retrieved 9 November 2016.
9. "Demonetisation: Chaos grows, queues get longer at banks, ATMs on weekend". 12 November 2016.